वर्ष-9 | अंक 29 | 10 मार्च से 16 मार्च 2025 तक | पृष्ठ-12 | MPHIN/2015/63623

न्यूज क्राइम फाइल

आमंत्रण मुल्य 15/-

ग्वालियर, भिंड, मुरैना, छतरपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, सिवनी, जबलपुर, रीवा, सतना, होशंगाबाद, हरदा एवं इंदौर में प्रसारित।

एमपी में धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा

सीएम बोले- ऐसे दुष्कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा; महिला दिवस पर लाड़ली बहनों को राशि ट्रांसफर

उदय प्रताप सिंह चौहान

शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं। ऐसे दुष्कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना के 1250 रुपए ट्रांसफर किए। सिंगल क्लिक में मार्च 2025 की लगभग 1552.73 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शनधारक महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए भी राशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान सीएम की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की कमान महिला अधिकारियों के हाथों सौंपी गई। सीएम ने महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता और साहसिक कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, निर्मला भूरिया, सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी और विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे।

नारी सशक्तिकरण को लेकर जो भी हो सकता है कर रहे

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, महिला बाल विकास, पुलिस विभाग और ग्रामीण एवं पंचायत विभाग का संयुक्त आयोजन किया गया। इसमें नई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। महिलाओं की नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए गए। सीहोर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 200 से ज्यादा ई-साइकिल दी गईं। लाड़ली बहनों और उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी महिलाओं को राशि ट्रांसफर की गई। मुझे बताया गया है कि स्व-सहायता समूह के माध्यम से हमारे प्रदेश में लखपति दीदियां बनी हैं। नारी सशक्तिकरण को लेकर जो भी हो सकता है हमारी सरकार कर रही है।

महिलाएं संभाल रहीं सीएम की सुरक्षा की कमान

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीएम डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा और कारकेड सहित अन्य व्यवस्थाओं की सारी कमान महिलाएं संभाल रही हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी उप पुलिस अधीक्षक बिट्टू शर्मा के पास है। वहीं मुख्यमंत्री का वाहन इंस्पेक्टर इरशाद अली चला रही हैं। कारकेड के वाहनों की जिम्मेदारी सपना सहित अन्य महिला चालकों पर है। ओएसडी का दायित्व अंडर सेक्रेटरी श्रीलेखा श्रोत्रिय निभा रही हैं। प्रेस अधिकारी की जिम्मेदारी बिंदू सुनील और सोनिया परिहार के पास है।

सीएम ने महिला अधिकारियों को मंच पर बैठाया

सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी समेत अन्य महिला अधिकारियों को मंच पर बैठाया। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान वे मंच के सामने बैठी थीं। इस पर सीएम ने उन्हें मंच पर आने का इशारा किया।

प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लखपति दीदियां

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, महिला बाल विकास, पुलिस विभाग और ग्रामीण एवं पंचायत विभाग का संयुक्त आयोजन किया गया। इसमें नई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। महिलाओं की नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए गए। सीहोर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 200 से ज्यादा ई-साइकिल दी गईं। लाड़ली बहनों और उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी महिलाओं को राशि ट्रांसफर की गई। मुझे बताया गया है कि स्व-सहायता समूह के माध्यम से हमारे प्रदेश में लखपति दीदियां बनी हैं। नारी सशक्तिकरण को लेकर जो भी हो सकता है हमारी सरकार कर रही है।

सीएम बोले- राष्ट्रपति देश को गौरवान्वित कर रहीं

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, कितना सुखद संयोग है कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रित देश को गौरवान्वित कर रही हैं।

सीएम ने गैस रिफिलिंग के लिए राशि ट्रांसफर की

लाड़ली बहना योजना की राशि ट्रांसफर करने के बाद उज्जवला योजना की गैस कनेक्शनधारक महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए भी राशि ट्रांसफर की गई।

लाड़ली बहनों को ट्रांसफर की राशि

सीएम डॉ. यादव ने महिला दिवस के अवसर पर 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना की राशि ट्रांसफर की। सिंगल क्लिक में मार्च 2025 की लगभग 1552.73 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई।

महिलाएं संभाल रहीं सीएम के सुरक्षा

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज सीएम डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा और कारकेड सहित अन्य व्यवस्थाओं की सारी कमान महिलाएं संभाल रही हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी उप पुलिस अधीक्षक बिट्टू शर्मा के पास है। वहीं मुख्यमंत्री का वाहन इंस्पेक्टर इरशाद अली चला रही हैं। कारकेड के वाहनों की जिम्मेदारी सपना सहित अन्य महिला चालकों पर है। ओएसडी का दायित्व अंडर सेक्रेटरी श्रीलेखा श्रोत्रिय निभा रही हैं। प्रेस अधिकारी की जिम्मेदारी बिंदू सुनील और सोनिया परिहार के पास है।

सीएम ने महिला अधिकारियों को मंच पर बैठाया

सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी समेत अन्य महिला अधिकारियों को मंच पर बैठाया। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान वे मंच के सामने बैठी थीं। इस पर सीएम ने उन्हें मंच पर आने का इशारा किया।

फरवरी में ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर IMF के शानदार observations हम सबके सामने हैं।
इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच के 10 वर्षों में भारत की economy ने 66% की growth दर्ज की है।

गोपाल भार्गव -विधायक रहली, पूर्व मंत्री

उमंग सिंघार बोले-मरीजों के बिस्तरों पर चूहे घूम रहें

वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा; राजगढ़ में बच्ची की मौत पर पटवारी का हमला

न्यूज क्राइम फाइल

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत पर कांग्रेस ने मोहन सरकार को घेरा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अस्पतालों में चूहों के आतंक और बच्चा वार्ड की अव्यवस्था को उजागर करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऑक्सीजन की कमी से एक बच्ची की मौत के मामले में सरकार और अफसरशाही की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा- मंडला जिला अस्पताल के बच्चा वॉर्ड में शिशुओं की बजाय चूहों का आतंक है। यह स्थिति न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि अस्पतालों की खस्ता हालत की पोल भी खोल देती है। मरीजों के बिस्तरों पर चूहे घूमते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे मरीजों में भय का माहौल बन गया है। यह हालात दर्शाते हैं कि सरकारी अस्पतालों की सफाई और देखभाल के नाम पर किए सरकार के वादे झूठे हैं। इसका वीडियो भी सिंघार ने एक्स पर शेयर किया है।

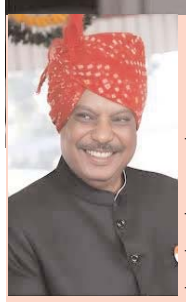

सिंघार ने आगे लिखा

अब जबकि कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने अस्पताल प्रबंधन को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या प्रबंधन को मंत्री के आदेश का इंतजार करना जरूरी था ? क्या यही स्थिति तब तक रहती, अगर मंत्री की नजर नहीं पड़ती?। आगे उन्होंने कहा- सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाए, न कि सिर्फ घटना के बाद औपचारिकता निभाने तक सीमित रहे। इन अस्पतालों में चूहों का आतंक और बुनियादी सुविधाओं की कमी, यह सब दर्शाता है कि प्रशासन को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे।

जीतू पटवारी ने बच्ची की मौत पर सरकार को घेरा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा- राजगढ़ जिला अस्पताल से भोपाल रेफर की गई तीन साल की बच्ची की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से मौत हो गई। एम्बुलेंस कर्मचारी बच्ची को ब्यावरा सिविल अस्पताल के गेट पर छोड़कर भाग गए। न तो रेफर पर्चा दिया और न ही मौत से लड़ती बच्ची को भर्ती करवाया। डॉ मोहन यादव की सरकार को देखना चाहिए कि जान बचाने वाले मासूमों की जान ले रहे हैं और मासूम की टूटी सांसें एक और दर्दनाक सरकारी हत्या का सबूत भी दे रही हैं, लेकिन सीएम बेफिक्र हैं। मत के मद में मस्त बीजेपी भी ठप्पे से सत्ता की कलंकित कुर्सी पर बैठी हुई है। जंगलराज की कोई जांच, कोई सजा, कोई भी मुआवजा अब पीड़ितों के छलनी मन पर मरहम नहीं लग सकता, ये हत्याएं कब रुकेंगीं?

1.80 करोड़ का मकान समेत 2.36 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच

भोपाल में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा पर आयकर विभाग की कार्रवाई

न्यूज क्राइम फाइल

आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति विंग ने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक राजेश शर्मा और ग्रुप की 2.36 करोड़ की प्रापर्टी अटैच कर ली है। यह प्रापर्टी अब राजेश शर्मा और उसके सहयोगी बेच नहीं सकेंगे। इसके पहले आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेटिंग विंग भी शर्मा की कई प्रापर्टी अटैच कर चुकी है। दोनों विंग ने प्रॉपर्टी अटैच करने की अलग-अलग कार्रवाई की हैं। ताजा मामले में आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति विंग ने कस्तूरबा नगर में राजेश शर्मा की तीन मंजिला इमारत को भी अटैच कर लिया है। अकेले इसी प्रापर्टी की वैल्यू 1.80 करोड़ रुपए है। बता दें कि प्रदेश में आयकर विभाग ने 18 दिसम्बर को त्रिशूल

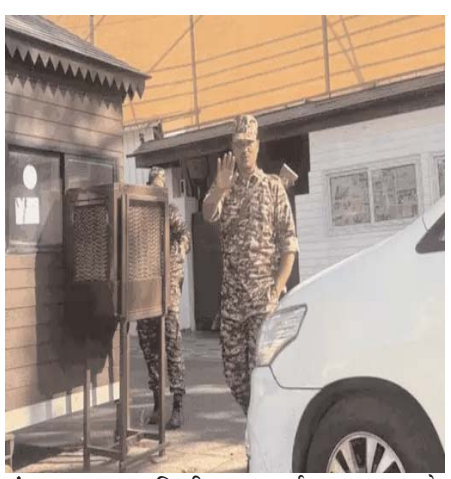

कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप, ईशान ग्रुप के संचालकों के 56 ठिकानों पर छापेमारी की थी। भोपाल के 53 और इंदौर के दो व ग्वालियर के एक ठिकाने पर की गई छापेमारी में आयकर विभाग को 10 करोड़ रुपए कैश और 25 से ज्यादा लॉकर की जानकारी मिली थी।

आयकर की परमिशन के बगैर नहीं होगी खरीदी-बिक्री

आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेटिंग विंग ने प्रदेश के पंजीयन कार्यालय को पत्र लिखकर प्रापर्टी अटैच किए जाने की जानकारी दी थी। अब आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति विंग ने भी जांच के बाद 2 करोड़ 36 लाख रुपए कीमत की भूमि और मकान संबंधी बेनामी प्रापर्टी अटैच कर ली है। चार माह के लिए अटैच की गई इस प्रापर्टी को आयकर विभाग की परमिशन के बिना बेचा या खरीदा नहीं जा सकेगा। राजेश शर्मा के घर आयकर छापेमारी के बाद जांच में खुलासा हुआ है कि अपने ही लोगों के माध्यम से बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी-बेची थी। बरखेड़ा नाथू की प्रॉपर्टी के मामले में यह बात सामने आई है कि राजेश शर्मा ने दीपक तुलसानी के नाम की जो प्रॉपर्टी खरीदी उसका पेमेंट संजय मीणा के माध्यम से पहले राजेश तिवारी को कराया और फिर राजेश तिवारी के माध्यम से शर्मा की पत्नी राधिका के खाते में पैसा जमा कराकर खरीदी बताई गई। आयकर की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरा लेन-देन राजेश शर्मा के द्वारा ही किया गया है। इसके बाद प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया।

जनवरी 2025 में आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने राजेश शर्मा और उसकी पत्नी राधिका शर्मा की प्रापर्टी अटैच की थी। राधिका शर्मा के नाम पर 16 और राजेश शर्मा के नाम पर 8 प्रापर्टी की सूची पंजीयन विभाग को भेजी गई है।

जहां विजन है, वहीं इनोवेशन भी है...इनोवेशन और विजन के साथ टेक्नोलॉजी मिल जाए तो समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकता है...

योगी आदित्यनाथ- मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश

माधव नेशनल पार्क होगा प्रदेश का 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र : मुख्यमंत्री

न्यूज क्राइम फाइल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत में टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर चुके मध्यप्रदेश को जल्द ही एक नए टाइगर रिजर्व पार्क की सौगात मिलने जा रही है। शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र होगा, जो चंबल क्षेत्र में वन्य जीव प्रेमियों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे स्वयं बाघों का एक जोड़ा माधव नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। चंबल रेंज में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। एशिया में पहली बार चीते भी चंबल के कूनो नेशनल पार्क में दिखाई दे रहे हैं। चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियाल एवं डॉल्फिन प्रोजेक्ट पर भी कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मीडिया को जारी संदेश में कहा कि देश में सबसे ज्यादा टाइगर मध्यप्रदेश में हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मध्यप्रदेश आते हैं। बाघ संरक्षित क्षेत्र में जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए सभी नेशनल पार्कों में सीजन भर पर्यटकों का आवागमन रहता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में बाघों की संख्या और उनके संरक्षण से प्राप्त उपलब्धियों पर

प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के पर्यटन व संस्कृति पर केंद्रित सत्र में कहा था कि मेले का मतलब है मेल-जोल बढ़ाना और ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट, उद्योगपतियों-निवेशकों-उद्यमियों और सरकार व प्रदेशवासियों के बीच मेल-जोल बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। भोपाल में पहली बार आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश दुनिया के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक, यंग इन्नोवेटर, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुसार निवेश के इस महाकुंभ में पधार रहे सभी अतिथियों का स्वागत-सत्कार, भारतीय संस्कृति के अतिथि देवो भव: का भाव जीआईएस में साकार हुआ। उनका विचार था कि यह आयोजन परस्पर मेल-जोल, सद्भावना और सुखद अनुभूति के साथ हो और समिट की सुमधुर स्मृतियां, लंबे चलने वाले संबंधों का आधार बनें। अत: इस वैश्विक आयोजन में अतिथियों के आवागमन-आवास और भोजन की व्यवस्था के प्रति आरंभ से ही विशेष संवेदनशीलता रही।

वैश्विक सम्मेलन में, विविधता से भरे हमारे देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ दुनिया के लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भोजन, सभी की मूल आवश्यकता है, परंतु अलग-अलग सामाजिक -सांस्कृतिक-भौगोलिक परिवेश के कारण भोजन के लिए लोगों की आदतें, रुचियां और आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए इन विशिष्ट जन के लिए भोजन की व्यवस्था एक चुनौती थी। विविधता भरे समागम में सभी के स्वाद और संतुष्टि के अनुरूप भोजन की व्यवस्था करना, एक प्रकार से अपनी दक्षता का प्रमाण देने जैसा था। भोजन हमारी संपन्नता- सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यह माना जाता है कि भोजन में लोगों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। अच्छे स्वाद-सुगंध-स्पर्श और आकर्षक प्रस्तुतिकरण से भोजन की यह क्षमता और बढ़ जाती है। देश के दिल में बसे मध्यप्रदेश का भोजन, नए बदलावों को समरसता के साथ आत्मसात करने का प्रतीक है।

ऐशबाग फर्जी कॉल सेंटर...

फरार एएसआई की बर्खास्तगी की तैयारी, तलाश में दबिश, 3 आरोपियों को बचाने की हुई थी डील

न्यूज क्राइम फाइल

ऐशबाग में पकड़े गए फर्जी कॉल सेंटर में एक नहीं, तीन आरोपियों को बचाने की डील हुई थी। इसमें मास्टरमाइंड अफजल का साला मुइन, उसकी पत्नी जायद बेगम और उसका भाई वसीम खान शामिल हैं। डील करने वाले आरोपी एएसआई पवन रघुवंशी ने इन सभी को आरोपी न बनाने का भरोसा दिलाया था।

इसका जिक्र एफआईआर में किया गया है। इस मामले का मुख्य आरोपी पवन अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसकी तलाश के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। शुक्रवार को इन टीमों ने पवन के हर संभावित ठिकाने पर दबिश दी। इधर, महकमे ने आरोपी पवन को बर्खास्त करने की तैयारी कर ली है।

गुरुवार तक आला अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटने वाले आरोपी टीआई

जितेंद्र गढ़वाल शुक्रवार को अंडरग्राउंड हो गए हैं। आरोपी एएसआई मनोज सिंह और प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र पहले से अंडरग्राउंड हैं। डील की रकम लाने वाले भाजपा पार्षद अंशुल जैन और जायद की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीम टीकमगढ़ रवाना की गई हैं।

किसकी क्या भूमिका थी...

■एएसआई पवन रघुवंशी- तीन आरोपियों को बचाने के लिए 25 लाख की डील की। 4.94 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। अभी फरार है।

■टीआई जितेंद्र गढ़वाल- आरोपी पवन ने बताया था- उसने डील टीआई जितेंद्र गढ़वाल के कहने पर की। टीआई को इसकी जानकारी थी।

■एएसआई मनोज सिंह- बिचौलिए से मीडिएशन का काम इसे ही दिया गया था।

■प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र- इसे भी मीडिएशन का काम दिया गया था।

■अंशुल जैन- टीकमगढ़ से भाजपा पार्षद है। डील की रकम यही लेकर आया था, फरार है।

टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को मिली एक और टाइगर रिजर्व की सौगात

वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष - भाजपा मप्र

आलेख

वर्चस्व पर संकट का कवच बनती हिंदी विरोध की राजनीति

हिंदी को लेकर तमिलनाडु की राजनीति का आक्रामक होना कोई नई बात नहीं है। हिंदी के विरोध में जिस तरह स्टालिन ने रोजाना आधार पर मोर्चा खोल रखा है, वह 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की याद दिला रहा है। संवैधानिक प्रावधानों की वजह से 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर जिम्मेदारी संभालनी थी, जिसके विरोध में सीए अन्नादुरै की अगुआई में पूरी द्रविड़ राजनीति उतर आई थी। तब हिंदी विरोध के मूल केंद्र में तमिल उपराष्ट्रीयता थी। उसके लिए तब यह साबित करना आसान था कि उस पर हिंदी थोपी जा रही है। तब आज की तरह सूचना और संचार की सहूलियतें नहीं थीं, तब दक्षिण और उत्तर के बीच आज की तरह सहज संचार नहीं था, तब आज की तरह मीडिया का इंटरनेटी वितान नहीं था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। लिहाजा इस संदर्भ में स्टालिन के मौजूदा हिंदी विरोध की तह में जाना जरूरी हो जाता है। चाहे तमिलनाडु का निवासी हो या फिर उत्तर भारत के किसी हिंदीभाषी इलाके का, उसके हाथ में अगर फोन है, उसमें अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो तय है कि उसकी उंगलियों के नियंत्रण में हिंदी और अंग्रेजी ही नहीं, दुनियाभर की भाषाएं हैं। इसलिए कम से कम सूचना और संचार के ऐसे माध्यमों पर किसी सरकार की वजह से भाषायी बंधन आज के दौर में हो भी नहीं सकता। इंटरनेट क्रांति के पहले भाषाओं के विस्तार में बाजार ने जो भूमिका निभाई, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज का बाजार वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के पंखों के सहारे कहीं और तेजी से फैल तो रहा ही है, फल-फूल भी रहा है। इसलिए हिंदी ही नहीं, किसी भी भाषा का विरोध अब दुनिया के किसी भी कोने में पूरी तरह न तो सफल हो सकता है और कोई दीवार उसे रोक सकती है। बेशक तमिलनाडु भाषायी स्तर पर अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन वह भी हमारे देश का हिस्सा है। मौजूदा स्थिति में तेजी से विकसित होता राज्य है और उसे अपने उत्पादन केंद्रों के लिए कामगारों की जरूरत है। जिसकी आपूर्ति उत्तर भारत के ही राज्य करते हैं। उसके निजी शैक्षिक केंद्रों के लिए विद्यार्थियों की भी जरूरत है। उत्तर भारत की जो शैक्षिक स्थिति है, उसकी असलियत सबको पता है। इस वजह से उत्तर भारतीय छात्रों की आवक भी तमिलनाडु में खूब है। ऐसे माहौल में वैसे तो हिंदी विरोध के औचित्य पर ही सवाल है। फिर भी स्टालिन विरोध कर रहे हैं तो उसके अपने कारण हैं। संचार और सूचना क्रांति और तेज आवागमन के चलते भाषायी स्तर पर तमिलनाडु की स्थिति तीन-चार दशक पहले जैसी नहीं है। वहां हिंदी बोलने वालों की संख्या भले कम हो, लेकिन उसे समझने और हिंदी में आने वाले सवालों का जवाब देने या प्रतिक्रिया में सौदा-सुलफ मुहैया कराने वालों की तादाद बढ़ी है। हिंदी या कोई अन्य भाषी वैसे भी तमिल संस्कृति को इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तमिल संस्कृति और भाषा दुनिया की पुरानी संस्कृतियों में से एक है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तमिल लोग अपनी संस्कृति और भाषा से नेह-छोह ही नहीं रखते, उसका शिद्दत से सम्मान भी करते हैं। फिर तमिलनाडु की ऐसी स्थिति नहीं है कि दिल्ली, जालंधर, सूरत, लुधियाना, मुंबई की तरह तमिलनाडु के शहरों में हिंदीभाषियों की बाढ़ आ जाएगी। वैसे एक बारगी मान लें कि जिन जगहों का जिक्र हुआ है, वहां हिंदीभाषियों की बाढ़ होने के बावजूद क्या वहां की स्थानीय संस्कृति और भाषाओं पर संकट आया। निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। दरअसल होता यह है कि बाहर से आया व्यक्ति स्थानीय संस्कृति और समाज के लिहाज से वहां व्यवहृत भाषा को अपने सामाजिक और सार्वजनिक कामकाज की भाषा बनाता है, वह अपनी बोली-बानी को अपने सीमित समाज और परिवार में इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसकी सार्वजनिक

संपर्क भाषा वहां की स्थानीय भाषा ही होती है। पता नहीं, इन तथ्यों को स्टालिन समझते हैं या नहीं, लेकिन वे बार-बार हिंदी पर आरोप लगाते रहते हैं कि वह तमिल संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगी। असल बात यह है कि तमिलनाडु की राजनीति में पिछली सदी के साठ के दशक से ही स्थानीय द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व बना हुआ है। कभी डीएमके तो कभी एआईडीएमके जैसी स्थानीय पार्टियां ही सत्ता की मलाई खाती रही हैं। सही मायने में देखें तो ये महज स्थानीय पार्टियां ही नहीं हैं, बल्कि अपने-अपने हिसाब से तमिल उपराष्ट्रीयता का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तमिल उपराष्ट्रीयता होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वह राष्ट्रीयता पर हावी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह कड़वा सच है कि तमिल उपराष्ट्रीयता राष्ट्रीय मूल्यों पर हावी रहती रही है। तमिल उपराष्ट्रीयता के ही जरिए द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज रही है। लेकिन संचार और सूचना क्रांति के दौर में अब तमिल उपराष्ट्रीयता वाली सोच को लगने लगा है कि अगर हिंदी आई तो उसके जरिए राष्ट्रीयता की विचारधारा मजबूत होगी। जिसका असर स्थानीय राजनीति पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा। हिंदी या किसी भी सामान्य संपर्क भाषा के ज्यादा प्रचलन से कट्टरतावदी स्थानीय सोच को चोट पहुंचेगी और इसके साथ ही तमिल माटी में राष्ट्रीय राजनीति की जगह मजबूत होगी। जिसका आखिर में नतीजा हो सकता है कि द्रविड़ राजनीति की विदाई। कह सकते हैं कि स्टालिन को यही डर सताने लगा है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला स्वीकार कर लिया, नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू होने दिया तो जिस स्थानीयता केंद्रित भावना प्रधान राजनीति वह या उनके साथी स्थानीय दल करते हैं, उसका प्रभाव छीजने लगेगा।

संपादकीय

बदले-बदले से 'सरदार' नजर आते हैं

इस शेयर में अगर 'सरकार' की जगह 'सरदार' लिख दिया जाए तो यह पंक्तियां पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान पर बिल्कुल स्टीक बैठती हैं। कुछ दिन पहले तक अपने चुटकलों से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले भगवंत मान अब उत्तर प्रदेश के योगी के अंदाज में दिखने लगे हैं। नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, दिन में हड़ताली राजस्व अधिकारियों को सीधा-सीधा धमकाते हैं कि 'आपको छुट्टी मुबारक' और शाम होते-होते उन्हें निलम्बित कर देते हैं। और तो और किसान नेताओं को यहां तक कहने लगे हैं कि 'बहुत हो चुका अब आपकी ब्लैकमेलिंग और नहीं चलेगी। आप लोगों ने पंजाब को धरना प्रदेश बना कर रख दिया है।' पंजाब में इन दिनों मुख्यमंत्री के व्यवहार में आए बदलाव के कारण खोजे जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुई पराजय के बाद पंजाब का नेतृत्व दबाव में है और कुछ कर दिखाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि राज्य में 'आप' की क्रान्तिकारी सरकार अपना आधे से अधिक कार्यकाल पूरा कर चुकी है परन्तु उपलब्धि के नाम पर सरकार के हाथ खाली-खाली से लगते हैं। क्रान्ति अब भ्रान्ति लगने लगी है। पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की छायाप्रति ही रही है। पंजाब में भी दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर आम आदमी क्लीनिक खोले गए, मनीष सिसोदिया के आदर्श स्कूलों की कॉपी करते हुए स्कूल आफ एमिनेंस खोले गए। पंजाब के मंत्री दिल्ली वालों की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते नहीं अघाते परन्तु दिल्ली के विकास मॉडल के धड़ाम होने के बाद पंजाब का नेतृत्व भी सन्न है। आम आदमी पार्टी की दृष्टि से पंजाब में तो स्थितियां और भी विकराल हैं क्योंकि यहां उसकी सरकार के कार्यकाल में नशा अपनी तमाम सीमाएं तोड़ता दिख रहा है, जबकि पार्टी नशामुक्ति के हिमालयी वायदे करके सत्ता में आई थी। पर आज राज्य में आए दिन कहीं न कहीं नशे की ओवरडोज मौत होने की खबरें मिलती रहती हैं। कुछ जगह पर तो आठ-दस साल के बच्चों के भी नशे करने की खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। राज्य में आटे की तरह चिट्टा (हेरोइन) बिक रहा है। नशा महिषासुर राक्षस बन चुका है जिसको जितना मारो उसके रक्त की हर बून्द से नए-नए महिषासुर पैदा हो रहे हैं। पुलिस आए दिन भारी मात्रा में नशा पकडऩे का दावा करती है परन्तु इसके बावजूद पंचनद की धरती पर नशे का छठा दरिया बहता दिखाई देता है। राज्य का सरकारी कर्ज निरंतर बढ़ रहा है तो महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देने का चुनावी वायदा विपक्षी दल भूलने नहीं दे रहे।

राजगढ़ जिला अस्पताल से भोपाल रेफर की गई तीन साल की बच्ची की एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से मौत हो गई!

जीतू पटवारी अध्यक्ष, मप्र कांग्रेस

सरकार ने किया नियमों में बदलाव, 800 वर्गफीट एरिया में बन सकेंगे सार्वजनिक चार्जिंग सेंटर

इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और सर्विस सेंटर के नियम बने

न्यूज क्राइम फाइल

प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने और अगले दो साल में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में डेवलप करने के फैसले के बाद मोहन सरकार ने चार्जिंग स्टेशन के लिए नए नियम तय कर दिए हैं। इसके लिए भूमि की उपलब्धता और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर के लिए नोटिफाइड एरिया तय कर दिए गए हैं। भूमि विकास नियमों में बदलाव करते हुए जारी नियमों में कहा गया है कि शहरों में 25 किमी की दूरी पर जनसंख्या के आधार पर चार्जिंग स्टेशन खोले जा सकेंगे। इसमें तय हुआ है कि करीब 800 वर्गफीट (74.5 वर्गमीटर) एरिया में सार्वजनिक चार्जिंग सेंटर बनाए जा सकेंगे। नगरीय विकास और आवास विभाग ने नगर व ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमों में संशोधन कर दिया है। इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग और सर्विस सेंटर के लिए विकास मानदंड तय किए गए हैं। इन नियमों में चार्जिंग स्टेशन और सर्विस सेंटर खोलने और चार्जिंग की व्यवस्था से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं।

इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर इन एरिया में खोले जा सकेंगे

- ■शहर के मध्य क्षेत्र
- ■उप मध्य क्षेत्र
- ■जिला केंद्र
- ■सामुदायिक केंद्र (केवल भराव केंद्र)

- ■नगरीय क्षेत्रों में आवासीय व औद्योगिक उपक्षेत्र
- ■राष्ट्रीय राजमार्ग या स्टेट हाइवे के किनारे, विकास केंद्रों के रूप में चिह्नित गांव
- ■माल परिवहन काम्पलेक्स
- ■प्रस्तावित मुख्य सड़कें

चार्जिंग व सर्विस सेंटर के लिए ये शर्तें भी होंगी लागू

- ■ईवी चार्जिंग स्टेशन और सर्विस सेंटर ऐसी सड़क पर स्थापित नहीं किया जाएगा जिस पर राइट आफ वे 30 मीटर से कम हो।
- ■पुराने नगरीय क्षेत्रों में जिम्मेदार अधिकारियों की स्वीकृति के आधार पर पुराने शहर के इलाकों में विशेष प्रकरणों पर विचार किया जा सकेगा।
- ■विस्फोटक और अग्निशमन विभाग द्वारा अनुमोदन के बाद ही सर्विस सेंटर और चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी दी जाएगी।
- ■सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र के अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर जलवायु नियंत्रण उपकरण और लिक्विड कूल्ड केबिल्स लगाना अनिवार्य होगा।
- ■सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र में ऐच्छिक अनुवृद्धि की जा सकेगी।

चार्जिंग और सर्विस सेंटर के लिए आवश्यक भूमि

- ■विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र (पीसीएस) बनाने के लिए कम से कम 13.5 गुणा 5.5 मीटर भूमि जरूरी होगी।
- ■फ्लूइड कूल्ट बैटरी चार्जिंग (एफसीबी), एक कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम (सीसीएस) तथा एक डीसी फाल्ट चार्जिंग मानक के लिए कम से कम 15 मीटर गुणा 7 मीटर जगह होना चाहिए।
- ■बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (ऑप्शनल) के लिए बैटरी फिटिंग के लिए चिह्नित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।

इस पर भी देना होगा ध्यान

- ■सरकार ने कहा है कि औद्योगिक उपयोग के लिए सुपर केरोसिन ऑयल और हल्के डीजल का भंडारण अलग से किया जाएगा।
- ■सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कनेक्शन और मीटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो सभी उपयोग करने वालों को 24 घंटे सातों दिन मिलेगी। फ्लूइड कूल्ड बैटरी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैप की उपलब्धता आवश्यक नहीं होगी और यह सर्विस प्रोवाइडर की इच्छा पर डिपेंड करेगी।
- ■फ्लूइड कूल्ड बैटरी चार्जिंग स्टेशन का आकार सर्विस प्रोवाइडर के तकनीकी निर्देशों के आधार पर बदला जा सकेगा।
- ■ईंधन भराव केंद्र आउटलेट्स सहित के संबंध में निर्देश व सुरक्षा मानक पेट्रोलियम नियमों और मानकों के संशोधनों के अनुरूप होंगे। सर्विस प्रोवाइडर को खुदरा आउटलेट्स या ईंधन भराव स्टेशन के साथ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी लेना होगी।
- ■कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के मामले में क्षेत्रीय पार्क विकसित जिला पार्कों को छोड़कर सभी एरिया उपयोग किए जा सकेंगे। साथ ही नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के किनारे, विकास केंद्रों के रूप में चिह्नित गांव, माल परिवहन काम्पलेक्स और प्रस्तावित मुख्य सड़कों को इसके लिए चुनाव जा सकेगा।
- ■इसके लिए सीएनजी मदर स्टेशन बनेगा जिसके लिए 1080 वर्गमीटर जमीन होनी चाहिए। भवन घटक, नियंत्रण कक्ष, कार्यालय, वितरण कक्ष, गोदाम, रसोई और शौचालय के लिए 36 मीटर गुणा 30 मीटर भूमि होना चाहिए।

पत्रकार बनने का सुनहरा अवसर

अगर आपके अंदर लिखने का कौशल है और पत्रकारिता में रुचि है, तो 'न्यूज क्राइम फाइल' को आपकी तलाश है। 'न्यूज क्राइम फाइल' से जुड़ कर आप हर माह दस हजार रुपये तक कमा सकते हैं। 'न्यूज क्राइम फाइल' भोपाल, ग्वालियर, सतना, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और नीमच में ब्यूरो ऑफिस खोलने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार तत्काल हमें अपना बॉयोडाटा मेल करें या व्हाट्सअप करें।

उदय प्रताप सिंह चौहान (संपादक) 07223003441

website: www.newscrimefile.com

email: newscrimefile@yahoo.com

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर लाड़ली बहनों को खुशियों की सौगात!%मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना% अंतर्गत कल 8 मार्च को खातों में आएगी सम्मान और स्वाभिमान की 22वीं किस्त...
मोहन यादव- सीएम मप्र

महिला आरपीएफ जवान अब मिर्च स्प्रे से होंगी लैस

यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे का नया फैसला, आत्मरक्षा की देंगे ट्रेनिंग

न्यूज क्राइम फाइल

महिला यात्रियों की सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक अहम कदम उठाया है। रेलवे सुरक्षा बल की महिला कर्मियों को अब मिर्च स्प्रे कैन से लैस किया जाएगा, जिससे वे आपातकालीन परिस्थितियों में अधिक सशक्त और प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकेंगी।

महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर

यह निर्णय विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिला आरपीएफ कर्मियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। भारतीय रेलवे ने यह कदम उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उठाया है, जहां महिला यात्री असुरक्षित महसूस कर सकती हैं। सुनसान रेलवे स्टेशन, चलती ट्रेनें और दूरस्थ स्थानों पर तैनात महिला आरपीएफ कर्मियों को मिर्च स्प्रे से लैस करना उन्हें संभावित खतरों से निपटने में मदद करेगा। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा,यह निर्णय महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक स्थलों को अधिक सुरक्षित बनाने के हमारे मिशन के अनुरूप है। महिला आरपीएफ

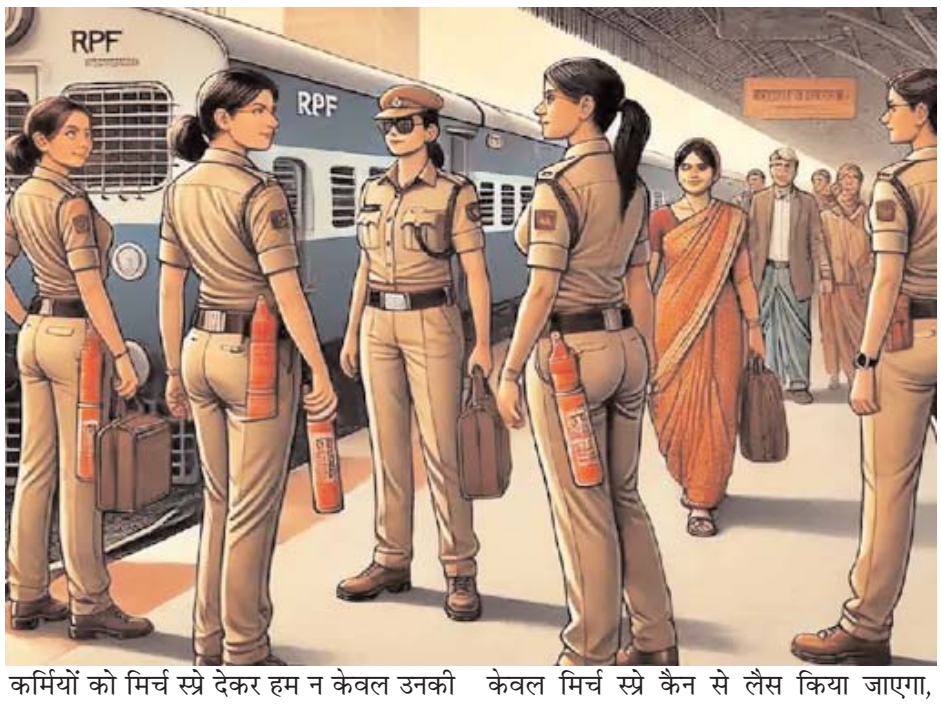

कर्मियों को मिर्च स्प्रे देकर हम न केवल उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रहे हैं।

भोपाल रेल मंडल में 45 महिला कर्मी तैनात

भोपाल रेल मंडल में कुल 500 से अधिक आरपीएफ जवान हैं, जिनमें करीब 45 महिला जवान कार्यरत हैं। इन महिला कर्मियों को न केवल मिर्च स्प्रे कैन से लैस किया जाएगा, बल्कि उन्हें आत्मरक्षा और संकट प्रबंधन की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे वे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकें।

मेरी सहेली टीम का अहम योगदान

भारतीय रेलवे महिला सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से सतर्क है। वर्तमान में आरपीएफ में 9% महिलाएं कार्यरत हैं, जो कि किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में महिलाओं का सबसे अधिक अनुपात है। इनमें से कई महिला आरपीएफ कर्मी मेरी सहेली टीम का हिस्सा हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ट्रेनों में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देशभर में 250 से अधिक मेरी सहेली टीमें प्रतिदिन लगभग 12,900 महिला यात्रियों से संपर्क स्थापित कर उनकी सहायता करती हैं। संकट की स्थिति में महिला आरपीएफ कर्मी तुरंत सहायता के लिए आगे आती हैं, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित यात्रा अनुभव मिलता है।

महिला सुरक्षा पर रेलवे की विशेष योजना

भोपाल रेल मंडल के कमांडेंट प्रशांत यादव ने बताया कि हाल ही में कुछ जोनों में महिला आरपीएफ कर्मियों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मिर्च स्प्रे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा,हमारी महिला कर्मी न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, बल्कि अन्य महिला यात्रियों में भी जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगी। इस पहल से न केवल महिला आरपीएफ कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि महिला यात्रियों को भी अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल मिलेगा।

सौजन्य भेंट

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ विधानसभा के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ शनिवार को गुर्जरबर्डिया मंडल अंतर्गत ग्राम रठाना में 1126.00 लाख की लागत से बनने वाले पीपल्या कराड़िया गांव से हाईस्कूल पहुंच मार्ग, लच्छाखेड़ी से नेतावली व्हाया रठाना मार्ग और खंडेरिया मारू से नावनखेड़ी मार्ग के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया और उपस्थितजन को बधाई दी।

सिलवासा के कार्यक्रम में अपार संख्या में आए अपने परिवारजनों के स्नेह और आशीर्वाद से अभिभूत हूं!

प्रधानमंत्री- नरेंद्र मोदी

बहू से गिफ्ट लेकर हुए भावुक; 1 घंटे में तैयार किया डांस; सिंधिया जोधपुर पहुंचे

बेटे की बारात में जमकर नाचे शिवराज सिंह चौहान

न्यूज क्राइम फाइल

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय की आज जोधपुर में शादी है। वे थोड़ी देर में लिबर्टी शू कंपनी के डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी अमानत के साथ उम्मेद भवन पैलेस में सात फेरे लेंगे। तीन दिन से चल रहे इस जलसे में आज कई वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हुए हैं, जिसमें मप्र और राजस्थान भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हैं। गुरुवार शाम कार्तिकेय की बारात निकली, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जमकर नाचे। उनके साथ छोटे बेटे कुणाल भी खूब थिरके।

इससे पहले बुधवार को मेहंदी और संगीत सेरेमनी हुई। इस दौरान शिवराज ने बेटे-बहू को नया जीवन शुरू करने से पहले सीख देते हुए कहा कि आप अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं। जीना उसका जीना है, जो औरों के लिए जिएं। बुधवार को शिवराज का जन्मदिन भी था, संगीत सेरेमनी में कार्तिकेय-अमानत ने उन्हें रामचरित मानस गिफ्ट में दी तो वे भावुक हो गए। संगीत कार्यक्रम में शिवराज पत्नी साधना सिंह के साथ चांद सा रोशन चेहरा गाने पर थिरकते दिखे, तो साधना सिंह ने अपनी दोनों बहुओं के साथ मेरे घर आई एक नन्ही परी..गाने पर डांस किया। दूल्हा-दुल्हन ने भी कपल डांस किया।

साधना सिंह ने कहा- एक घंटे में तैयार किया डांस

मैंने सिर्फ एक घंटे में डांस तैयार किया है। इनको टाइम मिलता नहीं है। आज इनका जन्मदिन है और बेटे का संगीत है तो डांस तो करना है। फिर जब दोनों डांस करने लगे तो शिवराज ने कहा कि मैं पूछ रहा हूं कि मुझे क्या करना है। इस पर सब खिलखिलाकर हंसने लगे।

केन्द्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक, दो रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
केंद्रीय गृहमंत्री-अमित शाह

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में राज्य के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भावी वित्तीय आवश्यकताओं की जानकारी दी।

फ्री-बीज स्कीम पर बोलने से बचे 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष

न्यूज क्राइम फाइल

16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढिया ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही फ्री बीज स्कीम को लेकर आयोग ने अभी तक कोई अनुशंसा तय नहीं की है। इसको लेकर आयोग के सभी पांचों सदस्य आपस में बैठक कर विचार करेंगे। आयोग के अध्यक्ष ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को राज्य सरकार के साथ बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों के जबाव दिए। फ्री बीज को लेकर किए गए सवाल पर पहले तो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का बताकर कुछ कहने से मना कर दिया लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि अधिकांश राज्य सरकारें फ्री-बीच स्कीम को बढ़ावा दे रही हैं तो क्या ऐसे मामलों में आयोग अपनी सिफारिश देगा। इस पर उन्होंने सदस्यों की बैठक में विचार करने की बात कही। कन्वेंशन सेंटर की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, मंत्री, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के अधिकारियों ने आगामी पांच साल की कार्ययोजना पर बातचीत की। इसमें सामने आया कि मध्यप्रदेश सरकार आदिवासी विकास पर और भविष्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करने वाली है। राज्य सरकार अपने टैक्स से खुद के लिए आत्मनिर्भर बना सके इस पर इस पर भी बात हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि आयोग ने एमपी के 2047 के रोडमैप को सराहा है। इसके साथ ही सीएम ने किसानों को तीन साल में 30 लाख किसानों को सोलर पंप देने सहित जन, जल, जंगल, जमीन और जैविक विविधता का संरक्षण करने की बात कही।

भविष्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस

अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि एमपी बीसवां राज्य है जहां आयोग ने विजिट कर सुझाव लिए हैं। ग्रांट को लेकर कई मामलों

में सुझाव आए हैं, राज्य सरकार से कई प्रस्ताव मिले हैं। यहां इसको लेकर काफी मजबूत प्रजेंटेशन आए, जिसमें पता चला कि 15 सालों में कृषि और अन्य सेक्टर में एमपी ने कैसे छलांग लगाई है। भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें इकॉनामी डेवलपमेंट पर फोकस है। विकसित मध्यप्रदेश के लिए हाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से एमपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ावा आना तय है। वर्टिकल डिवोल्यूशन को लेकर एमपी सरकार ने रिकमंडेशन दी है, इसे आयोग ने देखा है। एमपी में सेस और सरचार्ज 10 प्रतिशत रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री बोले- आयोग ने कार्य को सराहा

बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि आयोग के समक्ष एमपी सरकार की ओर से दिए गए प्रजेंटेशन की आयोग ने सराहना की है। अफसरों ने विस्तार से अलग-अलग कामों के जानकारी आयोग को दी है। आयोग ने एमपी की तैयारियों की प्रशंसा की है।

केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़े- सीएम यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसलिए इसकी जरूरतें भी बड़ी हैं। सबके कल्याण के जरिए एक समतामूलक समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही केन्द्र और राज्य सरकारों का एकमेव लक्ष्य है। राज्यों की मजबूती में ही राष्ट्र की मजबूती है, इसलिए केन्द्रीय करों और राजस्व प्राप्तियों में राज्यों की हिस्सेदारी अर्थात् अनुदान बढ़ाया ही जाना चाहिए।

पंचशील के सिद्धांतों का पालन करना प्राथमिक लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पंचशील सिद्धांतों का पालन करते हुए जन, जल, जंगल, जमीन और जैविक विविधता का संरक्षण हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। जंगल बचेंगे तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जन-जीवन बचेगा। हम जैविक संपदा को संरक्षित रखने के लिए भी हर जरूरी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 18 नई औद्योगिक नीतियों के कारण निवेशक भी हमसे जुड़ रहे हैं। आरआईसी और जीआईएस के जरिए प्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। हम हर जिला कलेक्ट्रेट में उद्योग प्रकोष्ठ बना रहे हैं, इससे किसी भी निवेशक को जिला स्तर पर भी कठिनाई नहीं आएगी।

महाराष्ट्र सरकार के साथ ताप्ती नदी परियोजना पर काम

16 वें वित्त आयोग के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अभी हमारा बजट करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए है। अगले पांच सालों में हम इस बजट को बढ़ाकर दोगुना कर देंगे। उन्होंने वित्त आयोग से कहा कि मध्यप्रदेश नदियों का मायका है और इसीलिए हम नदियों को जोड़कर जल बंटवारे के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

सीएम बोले- तीस लाख किसानों को सोलर पंप देंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले तीन सालों में सभी 30 लाख किसानों को सोलर पम्प देंगे। इससे हमारे किसान अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जा दाता भी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को मात्र पांच रुपए में बिजली कनेक्शन देने जा रही है, इससे हमारे किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग को मेमोरेंडम की प्रति भी सौंपी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और वित्तीय सहयोग की जरूरतों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आयोग को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की भावी योजनाओं की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodiकी अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय कैबिनेट ने आज उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक, दो रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।इससे क्षेत्र में जहाँ पर्यटन को बढ़ावा को मिलेगा वहीं स्थानीय लोगों को मिलने वाले रोज़गार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

रक्षा मंत्री-राजनाथ सिंह

शिवराज बोले, अगले चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को

स्मार्ट पार्क में पौधरोपण के बाद महिलाओं से संवाद में कहा-बहनें गरीब, मजबूर क्यों रहें

न्यूज क्राइम फाइल

आगामी 2028-29 में होने वाले चुनाव 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के साथ होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण लेकर आए हैं। अगले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में 33 प्रतिशत सीटों पर बहनें मिलेंगी। इन चुनावों में आरक्षण के साथ महिलाएं सांसद, विधायक और मंत्री बनेंगी। महिलाएं भारत को समृद्ध बनाएंगी। महिलाओं का राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। देश में अभी डेढ़ करोड़ लखपति दीदी हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में जल्दी ही तीन करोड़ लखपति दीदी होंगी। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी के स्मार्ट पार्क में महिलाओं के साथ पौधरोपण के बाद मीडिया से कही। शिवराज सिंह ने बहनों से संवाद कर उनके अनुभव सुने। इस दौरान चौहान ने कहा कि बहनें गरीब क्यों रहें, उनकी आंखों में आंसू क्यों हों, वो मजबूर क्यों रहें, वह भी आर्थिक रूप से सक्षम बनें और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट रहे। इसमें भारत सरकार के ग्रामीण

विकास विभाग के अंतर्गत आजीविका मिशन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। शिवराज ने कहा कि आजीविका मिशन से आज 91 लाख महिला स्वयं-सहायता समूह पूरे देश में हैं जिससे लगभग 11 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं। हमारे ये समूह 745 जिलों के 7 हजार 138 ब्लॉक्स में फैले हुए हैं। हमारे क्लस्टर लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जो इन समूहों को संगठित करने का काम करते हैं। इन समूहों को, संस्थाओं को 50 हजार करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। बैंकों से भी सस्ती ब्याज दरों पर 10 लाख 14 हजार करोड़ रुपए दिलाए गए हैं। कोई दीदी बैंक सखी हैं, कोई कृषि सखी है, कोई टैक्स सखी है, कोई पशु सखी है, ये अलग-अलग कार्यों में लगी हुई हैं।

विकसित भारत बनाने में बहनों का योगदान होगा

केन्द्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से बहन-बेटियों का शैक्षणिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। अब अगले लोकसभा, विधानसभा चुनाव में 33ब सीटों पर यह बहनें ही चुनाव लड़ेंगी। ये सांसद, विधायक, मंत्री बनेंगी। बहनों, बेटियों की तकदीर भी बदलेगी और अपनी जिंदगी भी बदलेंगी और अपने देश को विकसित भारत के रूप में विकसित भारत बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा।

भिंड में युवक को मुर्गा बनाकर डंडे-बेल्ट से पीटाः गर्लफ्रेंड से मिलने यूपी से आया था; तंग आकर युवती ने घरवालों को बता दिया

न्यूज क्राइम फाइल

भिंड जिले के लहार थाना क्षेत्र के रहावली गांव में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए युवक को गांव के लोगों ने बेल्ट और डंडे से जमकर पीटा। स्थानीय युवकों ने उसे मुर्गा भी बनाया। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो शनिवार को सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला है। रिश्तेदारी के कारण उसका रहावली गांव में आना-जाना था। इस दौरान एक लड़की से उसकी बातचीत शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक लड़की से एकतरफा प्यार करता था। उसके बार-बार संपर्क करने से तंग आकर लड़की ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। इसके बाद शुक्रवार को जब वह मिलने की उम्मीद में गांव आया तो लड़की के परिजन और ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी।

मारपीट करने वालों की पहचान कर रही पुलिस

लहार थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। पुलिस युवक की पहचान और उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी जुटाने के साथ-साथ मारपीट करने वालों की भी पहचान कर रही है। जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

भिंड में सिर दीवार से लटका, धड़ जमीन पर मिला

न्यूज क्राइम फाइल। भिंड जिले के मेहगांव कस्बे के एक प्लॉट में बने कमरे में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो मृतक का सिर फंदे से लटका हुआ था, जबकि शरीर जमीन पर पड़ा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीआई शक्ति यादव ने बताया कि वार्ड क्रमांक 6 में स्थित एक प्लॉट में कमरा बना हुआ है, जिसकी छत का आधा हिस्सा खुला है। पिछले कुछ दिनों से वहां से दुर्गंध आ रही थी, जिससे आसपास के लोगों को संदेह हुआ। कमरे के बाहर ताला लगा था, जिससे लोगों को लगा कि अंदर कोई मृत जानवर होगा। लेकिन, जब प्लॉट मालिक ने ताला खोला, तो अंदर सियाराम ओझा निवासी औरैया, इटावा, उत्तर प्रदेश का शव पड़ा मिला। सिर फंदे पर लटका था, वहीं बॉडी जमीन पर पड़ी मिली।

20 दिन से था लापता

पुलिस जांच में पता चला कि सियाराम ओझा पिछले 20 दिनों से लापता था। शव की पहचान उसकी बहन सुखदेवी ने की। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जो विस्तृत जांच करेगी।

चमार स्टूडियो के संस्थापक सुधीर राजभर लाखों दलित युवाओं की कहानी को समेटे हुए हैं। वह अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, नए विचारों से भरपूर हैं और सफलता के लिए आतुर हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों तक पहुंच की कमी और सीमित अवसरों की चुनौती से जूझते रहे। नेता प्रतिपक्ष-राहुल गांधी

बोले- बिहार में लग रहा है जैसे महाकुंभ लगा हो

धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार, ढाई लाख लोग पहुंचे

न्यूज क्राइम फाइल

गोपालगंज के राम जानकी मठ में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा है। श्रद्धालुओं से पूरा पंडाल खचाखच भरा है, लोगों को बैठने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि करीब ढाई लाख लोग पहुंचे हैं। इनमें बिहार के अलावे यूपी और नेपाल के भी लोग हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने दिव्य दरबार कू शुरुआत करते हुए भोजपुरी ने कहा- का हाल बा, हमहु ठीक बा। हमारे सबसे लाडले बिहार के पगलन की जय। मुझे गाली देने वालों की भी जय। जिनको मेरे बिहार आने से पेट में दर्द हो रहा है उनकी भी जय। लोग कहते हैं कि बिहार आऊंगा तो जेल भेज देंगे। तुम लोग रोहिंग्या को रोक नहीं पाए। मैं तो भारत का हूं। रोक कर दिखाओ। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। बजरंग बलि का भक्त हूं। जब तक जिंदा हूं बिहार आऊंगा और दरबार लगाऊंगा।

हिंदू एक साथ हो जाएं तो देशद्रोहियों को भागना पड़ेगा

वहीं शुक्रवार को हनुमंत कथा के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू अकेला होगा तो भागना पड़ेगा, लेकिन सभी हिंदू एक साथ हो जाएं तो देशद्रोहियों को यहां से भागना

पड़ेगा। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करते हुए एकता का महत्व समझाते हुए मधुमक्खी और कुत्ते का उदाहरण दिया। कहा कि एक कुत्ता अकेला होने पर भाग जाता है, लेकिन मधुमक्खियां झुंड में होने के कारण इंसान को भागना पड़ता है।

भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हम मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहते हैं, रामराज से भरा हिंदुस्तान चाहते हैं। जात-पात को छोड़कर जब सारे सनातनी एक होंगे, तभी भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। उन्होंने कहा कि लोग बोलते हैं, मैं संविधान के खिलाफ बोलता हूं। मैं संविधान के खिलाफ नहीं हूं। एक हाथ में संविधान, दूसरे में भगवान लिए चलता हूं।

कथा के बीच भावुक हुए धीरेंद्र शास्त्री

कथा के बीच में धीरेंद्र शास्त्री भावुक हो गए। अपने पुराने दिन को याद करते हुए उन्होंने कहा, हमारे पिता जी को कोई शादी में नहीं बुलाता था। परिवार वाले अपनी शादी के कार्ड में पिताजी का नाम तक नहीं लिखते थे, क्योंकि हम गरीब थे। फटे कपड़े पहनकर चले जाएंगे तो उनकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन हमारी मां कहती थीं, तुम राम को कभी मत छोड़ना, हमारे दिन भी आएंगे।

ए ठठरी टिन शेड न तोड़ दियो

धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कई लोग उन्हें देखने के लिए टीन शेड पर खड़े हो गए। ये देखकर बाबा ने कहा, ओह, पगला, ठठरी... टीन शेड ना तोड़ दिओ...आराम से कथा सुनो।

पहली बार... 4 लाख करोड़ के पार जाएगा बजट

क्यूआर कोड स्कैन करते ही आपके हाथ में होगा मप्र सरकार का बजट

न्यूज क्राइम फाइल

मप्र विधानसभा का बजट 12 मार्च को जारी होगा। पहली बार मप्र सरकार बजट-पुस्तिका के साथ क्यूआर कोड भी जारी करेगी। क्यूआर कोड स्कैन करते ही सरकार की आमदनी, खर्च व विभागों को मिलने वाली धनराशि के आंकड़े मोबाइल पर देख सकेंगे। वित्त विभाग ने इस बार बजट की ई-बुक तैयार की है, जो क्यूआर कोड स्कैन करने पर मोबाइल फोन में दिखेगी। आम लोग इस ई-बुक को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव भी कर सकेंगे। क्यूआर कोड बजट जारी होने से एक दिन पहले सार्वजनिक स्थलों और सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे ही वित्त मंत्री बजट भाषण खत्म करेंगे, क्यूआर कोड सबकी पहुंच में होगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 12 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। 11 मार्च को 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, जो 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का होगा।

इस तरह बढ़ता गया बजट

2023-24 में राज्य सरकार ने 3.14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया था। 2024-25 में 16% की वृद्धि

दर के साथ 3.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया था। यदि यही वृद्धि दर बनी रहती है, तो 2025-26 के बजट का आंकड़ा लगभग 4.25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।

उज्जैन में अटैच करने का झांसा देकर बेची कारें

न्यूज क्राइम फाइल। उज्जैन में शासकीय कार्यालय में कार अटैच करने का लालच देकर 40 से अधिक कार मालिकों की कार औने-पौने दाम में बेचने वाले के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की है। उज्जैन पुलिस ने बेची गई करीब पौने दो करोड़ रुपए की 21 कार जब्त की हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी जगदीश परमार निवासी कालिदास मार्ग ने नई कारों को उसकी टीएनजी कंपनी में अटैच कर 25-30 हजार रुपए प्रतिमाह देने की बात कही थी। इसकी स्टांप पर लिखा पढ़ी हुई, जिसमें जगदीश ने अपनी कंपनी का नाम लिखा व स्वयं को प्रोप्राइटर बताया था। कंपनी का नानाखेड़ा क्षेत्र में ऑफिस खोला और एक के बाद एक करीब 40 नई कारों को कंपनी में अटैच कर लिया। एक दो माह रुपए भी दिए। बाद में रुपए देना बंद कर दिया। 17 लोग उसकी शिकायत लेकर नानाखेड़ा थाने पहुंचे। पुलिस केस दर्ज करने के बाद से उसकी तलाश कर रही थी। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी जगदीश परमार को गिरफ्तार कर लिया।

देश के टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है, जिससे निश्चित ही संपूर्ण क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
डिप्टी सीएम मप्र- जगदीश देवड़ा

रोशनपुरा चौराहे पर बनेगा कांग्रेस का स्टेट हेडक्वार्टर

कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स तोड़कर बनेगा 5 मंजिला ऑफिस

न्यूज क्राइम फाइल

बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपना नया हाईटेक ऑफिस बनाने की तैयारी कर रही है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर स्थित कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को तोड़कर नया प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) ऑफिस बनाने के प्लान पर काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि रोशनपुरा चौराहे पर बने कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है। ग्राउंड फ्लोर पर करीब 35 दुकानों में तमाम शो रुम संचालित हो रहे हैं। पीछे पार्किंग और सामने ओपन ग्राउंड हैं। इसी कॉम्पलेक्स को तोड़कर कांग्रेस का 5 मंजिला नया प्रदेश मुख्यालय बनाने की तैयारी है।

मौजूदा कार्यालय में विभाग रहेंगे संचालित

भोपाल में अभी जिस भवन में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय संचालित हो रहा है, वहां नया ऑफिस बनने के बाद प्रकोष्ठ और सामाजिक संगठनों के कार्यालय और जिला कार्यालय को शिफ्ट किया जा सकता है।

रोशनपुरा चौराहे पर है दो एकड़ जमीन

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार रोशनपुरा चौराहे पर पार्टी की करीब दो एकड़ जमीन है। भोपाल की सबसे प्राइम लोकेशन पर कांग्रेस की जमीन और कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स है। हालांकि, कई किराएदार ऐसे हैं जो सालों से किराया ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने अब अपनी जमीन पर

मुख्यालय बनाने की कवायद शुरू कर दी है। नए ऑफिस में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि संचालित नहीं होगी। यानि अब कांग्रेस अपने ऑफिस परिसर में किसी दुकान या शोरुम को किराए पर स्पेस नहीं देगी।

पूरे एमपी में कांग्रेस की संपत्तियों की कराई मैपिंग

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भोपाल सहित पूरे मप्र में कांग्रेस की संपत्तियों की मैपिंग कराई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों के साथ ही किस जिले में कांग्रेस की कितनी संपत्ति है। इसकी मैपिंग कराकर जानकारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को दिल्ली भेजी गई है। माना जा रहा है कि पीसीसी के बाद जिलों में भी कांग्रेस कार्यालयों का कायाकल्प कराया जा सकता है।

नए भवन में राष्ट्रीय नेताओं के ठहरने की होगी व्यवस्था

नए कांग्रेस स्टेट हेडक्वार्टर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवादल, किसान कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, एससी, एसटी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों और टीम के बैठने के लिए कक्ष बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय नेताओं के रुकने के लिए भी रुम बनाए जाएंगे। अभी बाहर से आने वाले नेताओं के लिए होटलों में कमरे किराए पर लेने पड़ते हैं। कई बार बड़े आयोजन होने के चलते नेताओं के लिए होटलों में कमरे बड़ी मशक्कत से मिल पाते हैं। अब ऑफिस में ही ठहरने की व्यवस्था होगी।

दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिलते ही शुरू होगा काम

एमपी कांग्रेस की ओर से नया ऑफिस बनाने का खाका तैयार कर लिया गया है। प्रॉपर्टी की मैपिंग के साथ ही नए प्रदेश कार्यालय की बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एआईसीसी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा।

पटवारी ने अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस मुख्यालय का कराया रेनोवेशन

जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की पूरी बिल्डिंग का रेनोवेशन कराया है। पीसीसी में कांग्रेस के विभाग, प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के चेंबर्स से लेकर स्टाफ के बैठने की व्यवस्था और इंटीरियर डेकोरेशन कराया गया है। सालों पुरानी लिफ्ट बदलकर नई लिफ्ट लगाई गई है।

मंत्री प्रहलाद पटेल के दामाद श्यामवीर बने बीडीए सीईओ

उज्जैन के अपर कलेक्टर को दतिया भेजा, रूही खान को उपसचिव एमएसएमई की जिम्मेदारी

न्यूज क्राइम फाइल

राज्य शासन ने भोपाल विकास प्राधिकरण के सीईओ और उज्जैन के अपर कलेक्टर को हटा दिया है। भोपाल विकास प्राधिकरण में अब आईएएस अफसर श्याम वीर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्याम वीर मंत्री प्रहलाद पटेल के दामाद हैं। वहीं दो माह से पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत रूही खान को भी सरकार ने काम सौंप दिया है। भोपाल विकास प्राधिकरण में करीब एक साल पहले प्रदीप जैन को सीईओ बनाया गया था। शुक्रवार को जारी आदेश में जैन को बीडीए सीईओ के पद से हटाकर मंत्रालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ कर दिया गया है। जैन की पोस्टिंग अभी मंत्रालय में किसी विभाग में नहीं की गई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन

में पदस्थ अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे को स्थानांतरित कर अपर कलेक्टर दतिया बनाया गया है। ये दोनों ही अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के हैं।

महिला दिवस के पहले रूही को मिला काम

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटीं आईएएस अधिकारी रूही खान को शासन ने उप सचिव एमएसएमई के पद पर पदस्थ किया है। साथ ही उन्हें उप सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें 31 जनवरी को भोपाल में उपस्थिति देने के एक माह से अधिक समय बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत आईएएस अफसर श्याम वीर को भोपाल विकास प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। दूसरी ओर 5 दिसम्बर 2024 से पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत आशीष भार्गव को अभी काम मिलना बाकी है।

कार्तिकेय और अमानत को आठवें वचन के रूप में प्रकृति की सेवा का वचन दिलाया। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रहे, इसलिए दोनों बच्चों ने अपने जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ सहित अन्य मंगल अवसरों पर पौधरोपण का संकल्प लिया है।
शिवराज सिंह चौहान-केंद्रीय कृषि मंत्री

पीएम मोदी ने डेढ़ लाख लखपति दीदियों से बात की

कहा- मैं दुनिया में सबसे अमीर, मेरे खाते में करोड़ों माताओं-बहनों का आशीर्वाद

संदीप कुमार सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी पहुंचे। खुली जीप में हेलीपैड से करीब 700 मीटर का रोड शो करते हुए वे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने डेढ़ लाख लखपति दीदियों से बात की। पीएम ने कहा- मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। क्योंकि, मेरे जीवन के खाते में करोड़ों माताओं-बहनों और बेटियों का आशीर्वाद जमा है। ये आशीर्वाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले मुझे महाकुंभ में मां गंगा का आशीर्वाद मिला है और आज मातृशक्ति का आशीर्वाद मिला है। लाखों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई पीएम ने कहा- अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को सभी अधिकार मिल गए हैं। पहले वहां महिलाएं मूलभूत सुविधाओं से वंचित थीं। पिछली सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं थी। हमने सरकार में आते ही सबसे पहले उन महिलाओं के लिए काम किया। इसके अलावा हमारी सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई। मातृत्व अवकाश 26 हफ्ते का किया पीएम ने कहा- चाहे

सामाजिक क्षेत्र हो या खेल का मैदान, महिलाएं देश के हर क्षेत्र में मौजूद हैं। 2014 के बाद से देश में महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री, 2019 में पहली बार हमारी संसद में 78 महिला सांसद चुनी गईं हैं। कामकाजी महिलाओं को पहले सिर्फ 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलता था। हमारी सरकार ने इसे 26 हफ्ते कर दिया है। महिलाओं के श्रम से देश का विकास हुआ पीएम ने कहा- आज के कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी महिलाओं ने अपने ऊपर ली। यह महिलाओं के ऊंचे आत्मविश्वास को दर्शाता है। भारत महिला नेतृत्व का एक महान उदाहरण है। महिलाओं के श्रम और पराक्रम से ही देश का विकास हुआ है। गुजरात के गांवों की लाखों महिलाओं ने आज दूध उत्पादन में क्रांति ला दी है। हमारी सरकार ने डेयरियों से दूध का पैसा सीधे बहनों के खाते में पहुंचाया। इसके अलावा कई योजनाओं का पैसा सीधे ट्रांसफर किया गया, जिससे बिचौलिए खत्म हो गए और इसका फायदा महिलाओं को मिला। महिला पुलिसकर्मियों का सिक्योरिटी कवर पीएम के इस मेगा इवेंट की खास बात ये है कि महिला दिवस के मौके पर केवल महिला पुलिसकर्मियों का सिक्योरिटी कवर तैनात किया गया है। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। 2,165 कांस्टेबल, 187 इंस्पेक्टर, 61 सब-इंस्पेक्टर, 19 डीएसपी, पांच डीएसपी, एक आईजी और एक एडीजी पीएम के हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल रही हैं।

मोदी ने महिला दिवस की बधाई दी, अपना सोशल अकाउंट वुमेन को सौंपा

मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया- महिला दिवस पर अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं! हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। आज, जैसा कि वादा किया गया था, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को उन महिलाओं द्वारा संभाला जाएगा जो अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब महिला अचीवर्स पीएम के सोशल मीडिया अकाउंट को संभालेंगी। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट को सात महिला अचीवर्स ने संभाला था।

राहुल बोले- गुजरात कांग्रेस के आधे नेता भाजपा से मिले

हमारे बब्बर शेर चेन से बंधे; यहां पार्टी नाकाम यह कहने में शर्म नहीं

न्यूज क्राइम फाइल

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की लीडरशीप में दो तरह के लोग हैं। उनमें बंटवारा है। एक हैं जो जनता के साथ खड़े हैं। जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। दूसरे हैं, जो जनता से कटा हुआ है दूर बैठता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। राहुल ने आगे कहा, मेरी जिम्मेदारी है कि जो ये दो ग्रुप हैं इनको छांटना है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। बब्बर शेर हैं लेकिन पीछे से चेन लगी हुई है तो वे चेन से बंधे हैं। यहां रेस के घोड़ों को बारात में बांध दिया जाता है। राहुल दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। शनिवार को दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने अहमदाबाद के जेड हॉल में प्रदेश के करीब 2 हजार कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महिला दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने महिला कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की।

1. गुजरात में कांग्रेस फेल, मुझे यह बोलने में कोई शर्म नहीं

गुजरात फंसा हुआ है, यह आगे बढ़ना चाहता है। गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। मैं ये बातें डरकर नहीं बोल रहा हूं और न शरमाकर बोल रहा हूं। मगर मैं आपके सामने ये बातें रखना चाहता हूं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हों, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिला पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम गुजरात की जनता की रिस्पेक्ट करते हैं, तो साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जनता की जो उम्मीदें हमसे थीं, मुझसे थीं, वे हम पूरी नहीं कर पाए। अगर ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से रिश्ता नहीं बनेगा।

2. पार्टी के अंदर दो तरह के लोग, इन्हें अलग करना होगा गुजरात की जो लीडरशीप है उसमें दो तरह के लोग हैं। जब तक अपने इन दो ग्रुपों को अलग नहीं किया तब तक गुजरात की जनता हम में विश्वास नहीं करेगी। गुजरात के किसान, मजदूर, स्टूडेंट विकल्प चाहते हैं न कि बी टीम। तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो ये दो ग्रुप हैं इनको छांटना है।

पार्टी से 30-40 लोगों को निकालना पड़े, तो वो भी करेंगे

कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर नेता हैं, बब्बर शेर हैं लेकिन पीछे से चेन लगी हुई है तो वे बंधे हैं। जनता ये देख रही है। हमें जनता से रिश्ते बनाना है तो पहला काम होगा कि, ग्रुप को अलग करना होगा। 30-40 लोगों को निकालना पड़े तो ये भी करेंगे। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, जाओ बाहर जाकर करो।

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक उदय प्रताप सिंह चौहान द्वारा कविता ऑफसेट प्रिंटर्स, एमपी नगर जोन -1 भोपाल (म. प्र.) से मुद्रित एवं 1209 पुष्पा नगर चांदबड़, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- उदय प्रताप सिंह चौहान, मो.7223003441 (प्रति सोमवार को प्रकाशित) समाचारों से संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं। (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।) RNI.NO MPHIN/2015/63623